आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, बुधवार 13 मई 2026

■ वर्ष : 5 ■ अंक : 168

■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

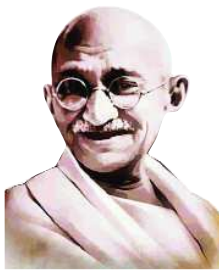

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला पर सुनवाई पूरी

पेज-2

मां बनना जिंदगी का सबसे सुंदर अनुभव- दीपिका सिंह

पेज-5

आईडीए की ईवी पहल बनी प्रदेश में मिसाल

पेज-6

न्यूज ब्रीफ

- 'मंदिर या मस्जिद, तेज आवाज में कहीं भी नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर', सीएम शुभेंदु का सख्त आदेश
- बारामती के गोजुबाबी गांव में आज सुबह ट्रेनिंग विमान क्रैश
- लखनऊ : अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन
- विदेश से सोना-चांदी मंगाना होगा महंगा, सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई
- रंगास्वामी आज पुडुचेरी सीएम के तौर पर लेंगे शपथ
- नॉर्वे और ईरान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा
- रूस इस साल तैनात करेगा नया सरमत परमाणु मिसाइल- पुतिन
- यूएई का बड़ा एक्शन, हिजबुल्लाह से जुड़े 16 लोगों और 5 संस्थाओं पर बैन
- ईरान की राजधानी तेहरान में भूकंप, 4.6 रही तीव्रता
- पीएम मोदी की अपील के बाद गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने रद्द किया यूएस दौरा
- ओपीईसी पर बोले ट्रंप, नाटो ने भी किया निराश
- कुवैत में 4 ईरानी नागरिकों की गिरफ्तारी पर तेहरान की सफाई

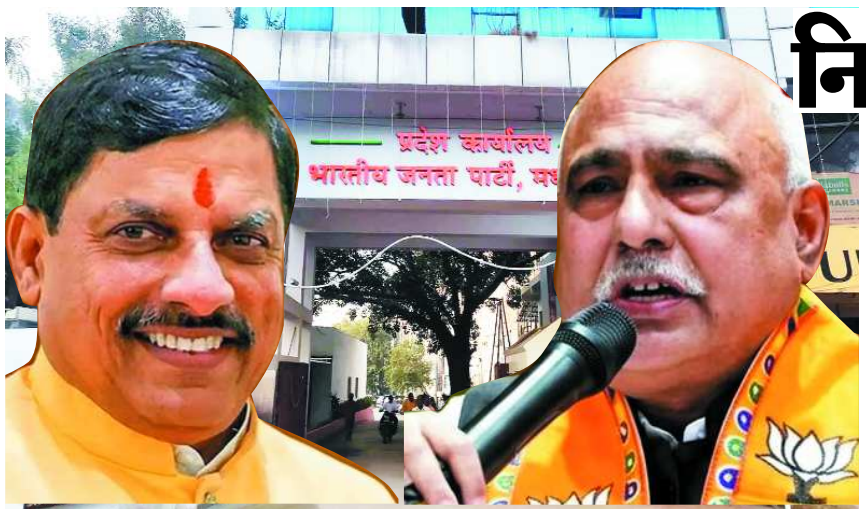

निगम मंडल की नियुक्ति पर प्रदेश संगठन का विराम

नियुक्तियों का अगले दौर के लिए कुछ दिन का इंतजार

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधानसभा चुनाव से ढाई साल पहले ही निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। अब तक करीब 70 नेताओं को विभिन्न पदों पर एडजस्ट किया जा चुका है। हालांकि, अब इन नियुक्तियों पर फिलहाल विराम लग गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। हेमंत खंडेलवाल से पूछा कि बचे हुए निगम-मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों में कब तक नियुक्तियां होंगी और यूपी की तरह मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, तो उन्होंने कहा- 'पहले आप (मीडिया) कहते थे कि गठन नहीं हो रहा। अब इतने सारे पद हमने दे दिए, अब तो कुछ विश्राम करने दीजिए। फिर नियुक्तियों का अगला दौर आएगा, तब फिर करेंगे।'

■ **बाल आयोग में सदस्यों में इनके नाम शामिल :** मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग में डॉ निवेदिता शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अभी सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए हैं। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष रहीं सीमा सिंह जादौन, सोनम निनामा, अर्चना गुप्ता, और अमरवाड़ा से बीजेपी की विधानसभा प्रत्याशी रहीं मोनिका बट्टी के नाम बाल संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में लगभग तय हो चुके हैं।

■ **इंदौर-भोपाल के प्राधिकरणों में नहीं हो पा रहे नाम तय :** ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ओरछा विकास प्राधिकरण सहित आधा दर्जन से ज्यादा प्राधिकरणों में नियुक्तियां नहीं हो पा रहीं हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण की रेस में शामिल चेतन सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में हुई बातों को लेकर प्रदेश संगठन से उनपर पार्टी विरोधी काम करने की शिकायतें की गई हैं।

बोर्ड

- मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड
- असंगठित कामगार बोर्ड
- गो पालन एवं पशु वर्धन बोर्ड
- समाज कल्याण बोर्ड
- म.प्र. राज्य हज कमेटी
- मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड
- मप्र राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ
- मप्र राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ

प्राधिकरण

- भोपाल विकास प्राधिकरण
- इंदौर विकास प्राधिकरण
- कटनी विकास प्राधिकरण
- बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण
- महाकौशल विकास प्राधिकरण
- राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण
- भरिया विकास प्राधिकरण

आयोग

- राज्य योजना आयोग
- राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग
- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग
- कृषक आयोग

निगम

- मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
- मप्र पर्यटन विकास निगम
- खनिज विकास निगम
- पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम
- मप्र ऊर्जा विकास निगम
- अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम
- हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
- कुक्कुट विकास निगम
- बीज विकास निगम
- मप्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

■ **150 से ज्यादा नेता होंगे एडजस्ट :** जो निगम, मंडल,बोर्ड, प्राधिकरण खाली पड़े हैं। उनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को मिलाकर करीब 150 से ज्यादा नेता एडजस्ट हो सकते हैं। अध्यक्ष के साथ एक से दो उपाध्यक्ष और 3 से 6 सदस्य नियुक्त किए जाने हैं।

10 प्राधिकरण, 8 निगम समेत अब तक 60 पद भरे

हाल ही में की गई नियुक्तियों में क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साफ नजर आया है। अब तक कुल 60 नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जिनमें 10 प्राधिकरण, 8 निगम, 5 आयोग, 4 बोर्ड, 3 समितियां और अन्य संस्थान शामिल हैं। इन नियुक्तियों में उज्जैन का दबदबा सबसे ज्यादा रहा है, जहां से 9 नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाकर मंत्री दर्जा दिया गया है।इन नियुक्तियों में मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उनके समर्थकों को प्रमुखता मिली है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी नेताओं को अच्छी हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए कई नेता अभी भी वेटिंग में हैं।

लंबे इंतजार के चलते दावेदारों में बेचैनी और निराशा

सूत्रों के मुताबिक पिछले कई महीनों से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े चेहरे इस पद के लिए सक्रिय हैं। कभी किसी पूर्व विधायक का नाम सामने आता है तो कभी संगठन के पुराने कार्यकर्ता का। लेकिन हर बार अंतिम सूची बनने से पहले मामला अटक जाता है। एक दावेदार ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि अब तो इंतजार की प्रत्याशा में यह हालात हो गई है कि संगठन इस पद पर किसी की भी नियुक्ति कर दे। बताया जा रहा है कि स्थानीय गुटबाजी, क्षेत्रीय संतुलन और दिल्ली स्तर की सहमति के कारण नियुक्ति लगातार टल रही है।

50 से ज्यादा नेता लॉबिंग में जुटे

अब तक जिन नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह नहीं मिल पाई है, वे बचे हुए निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में पद पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पार्टी और सरकार दोनों चाहते हैं कि नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़े, लेकिन अंदरूनी असहमति राह रोक रही है।

4 दिन तक हिटवेव की चपेट में रहेगा इंदौर

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मई महीने में गर्मी ने तीखे तेवर से आम लोगों को हलाकन कर दिया है। कल सुबह से ही सूरज का रौद्र रूप दिखा और शाम तक अधिकतम तापमान 43.2 डिसे से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। गर्म तेज हवा के थपेड़ों से लोग सिहर उठे। मौसम केंद्र के अनुसार, अधिकतम तापमान 43.2 डिसे दर्ज किया गया है जो कि अन्य दिनों की तुलना में 3 डिसे अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 24.7 डिसे दर्ज किया गया है जो कि अन्य दिनों की तुलना में सामान्य है। इस मौसम में दूसरी बार सबसे गर्म दिन सोमवार व मगंलवार रहा है। यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री पार कर गया, और एक ही दिन में गर्मी, बादल, लू के थपेड़े चले। रविवार को गर्मी ने दो साल का रिकार्ड तोड़ा।

गर्मी से बचाव जरूरी-मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिनभर पर्याप्त पानी पीएं, धूप में ज्यादा देर तक न रहें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। तेज धूप से बचने के लिए लोग और फेरीवाले सुबह एवं शाम को काम निपटा लेते हैं, वहीं जिन्हें परिस्थितिवश कामकाज करना है, उन्हें मुश्किलों का सामना कर भी काम करना पड़ रहा है।

अब सब्सिडी पर चलेगी सरकार की कैंची

एलपीजी सब्सिडी हो सकती है बंद!

नई दिल्ली (एजेंसी) ● पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने टैक्स रिकॉर्ड और एनर्जी डेटाबेस के बीच एक नया ऐलान किया है। वह एलपीजी सब्सिडी को लेकर एक अभियान को तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत तीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने उन उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जिनकी घरेलू आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक है।

तेल मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि तेल और गैस कंपनियां अब एलपीजी ग्राहकों के डेटाबेस का आयकर विभाग के रिकॉर्ड से सीधा मिलान कर रही हैं। इस वेरीफिकेशन से उन मामलों की पहचान होती है, जहां यूजर्स या उससे संबंधित परिवार के किसी सदस्य, जैसे कि पति और पत्नी, की कुल टैक्सेबल इनकम पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख की सीमा से अधिक हो गई हो। इसका मतलब है कि अगर किसी फैमिली की टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जाएगी और 7 दिनों के भीतर एलपीजी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। इससे बचने के लिए तुरंत आपको कार्यवाही करनी होगी।

डेटा को मैच करके तेल कंपनियां ऐसे लोगों को मैसेज अलर्ट भेज रही हैं। लोगों को भेजे जा रहे संदेश में लिखा है कि उपलब्ध आयकर रिकॉर्ड के अनुसार, आपकी (या आपके किसी संबंधित परिवार के सदस्य की) कुल टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये की तय सीमा से अधिक है। अगर तय अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो एलपीजी सब्सिडी बंद की जा सकती है।

आशंका : पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगे

पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार आपातकालीन आर्थिक उपायों पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है, ताकि तेल कंपनियों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर नियंत्रित रहे। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय चर्चा हुई है। तेल कंपनियां प्रतिदिन 1000 करोड़ रु. तक का नुकसान हो रहा है। इसे कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 8 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की जा सकती है।

स्कूल शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी ट्राइबल और शिक्षा विभाग होगा मर्ज

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मप्र सरकार प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विभाग और श्रम विभाग के सभी स्कूलों का संचालन अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में नीतिगत चर्चा कर इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। इसके बाद स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकार का मानना है कि अलग-अलग विभागों द्वारा स्कूल संचालन की वर्तमान व्यवस्था में कई तरह की असमानताएं हैं। अलग नीतियां, अलग मॉनीटरिंग और अलग प्रशासनिक व्यवस्था के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है।

इस कारण अब सभी सरकारी स्कूलों को एक समान व्यवस्था के तहत लाने की तैयारी की जा रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग पहले से करीब 92 हजार सरकारी स्कूल संचालित कर रहा है। इसके अलावा 145 मॉडल स्कूल और 274 सांदीपनि विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में करीब 81 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दूसरी ओर जनजातीय कार्य विभाग के पास 21 हजार से अधिक स्कूल हैं। अनुसूचित जाति विभाग का प्रत्येक संभाग में एक-एक स्कूल संचालित है, जबकि श्रम विभाग के चार श्रमोदय आवासीय विद्यालय-भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। इन सभी स्कूलों के मर्ज होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होने वाले स्कूलों की संख्या करीब 1.15 लाख तक पहुंच जाएगी।

सभी स्कूलों पर लागू होगी एक समान टांसफर पॉलिसी

मप्र में वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी अन्य विभागों से अलग है। जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विभाग और श्रम विभाग के स्कूलों पर यह पॉलिसी लागू नहीं होती। इस कारण शिक्षकों के तबादलों में अलग-अलग नियम लागू होते हैं और कई बार असमानता की स्थिति बनती है। सरकार अब इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। सभी स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल होने के बाद एक समान ट्रांसफर नीति लागू की जाएगी। इससे शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता आएगी और सभी शिक्षकों के लिए समान नियम लागू होंगे।

अगले सप्ताह आएगी तबादला नीति

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● अधिकारी कर्मचारियों को अपने तबादलों के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव ला सकती है। इस विषय पर मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक संवाद के दौरान चर्चा हुई। उन्होंने मंत्रियो से कहा कि वे लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की बचत के विभिन्न उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करें।

मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम ने अपने मंत्रियों के साथ कई अहम विषयों पर संवाद किया। इस दौरान नई तबादला नीति को लेकर चर्चा की गई। जनजातीय कार्यमंत्री विजय शाह ने कहा कि जो तबादला नीति आए, उसमें स्वैच्छिक आधार पर किए जाने वाले स्थानांतरण की सीमा (लिमिट) तय नहीं की जाए, जिससे जो लोग तबादला करना चाहते है, उनके स्थानांतरण हो सके। शाह के इस प्रस्ताव पर दूसरे मंत्रियों ने भी सहमति जताई, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले नीति आने दो, इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर से सामान्य प्रशासन विभाग को अगली बैठक में तबादला नीति लाने के निर्देश दिए।

न्यूज ब्रीफ

इंटरनेशनल नर्सेस डे पर केयर सीएचएल हॉस्पिटल्स में नर्सों का सम्मान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंटरनेशनल नर्सेस डे के अवसर पर केयर सीएचएल हॉस्पिटल्स, इंदौर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम 'अवर नर्सेस, अवर फ्यूचर : एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइफ' रखी गई। कार्यक्रम के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ की सेवाओं, मरीजों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान केक कटिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम में 40 नर्सों को उनके उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान अस्पताल परिसर में उत्साह और सम्मान का माहौल देखने को मिला।

कलेक्टर द्वारा यातायात सेल का गठन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर में सुव्यवस्थित यातायात के सुचारू रूप से संचालन की दृष्टि से यातायात सेल का गठन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गठित यातायात सेल में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोशन राय, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात संतोष कोल, नगर निगम के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, संयुक्त कलेक्टर ओम नारायण सिंह बड़कुल तथा नायब तहसीलदार महू देवेन्द्र कछायाा को शामिल किया गया है। यह यातायात सेल समय-समय पर सुचारू यातायात संचालन हेतु मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा तथा की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन आगामी होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

अवैध शराब परिवहन पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब जब्त

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● आबकारी विभाग इंदौर के देपालपुर वृत्त द्वारा अवैध मदिरा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक चार पहिया वाहन से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। कार्रवाई उप निरीक्षक भगवानदास अहरवार एवं उनकी टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में गश्त के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार टीम ने संदेह के आधार पर वाहन क्रमांकMP09 ZF7973 मारुति ईको वैन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में 15 बीयर पेटियों में रखी 360 केन 'बडवार्डजर मेग्नम इंटरनेशनल किंग ऑफ बीयर' बरामद हुई। उक्त शराब पर 'फॉर सेल इन हरियाणा' अंकित था, जिससे स्पष्ट हुआ कि इसे अवैध रूप से परिवहन कर इंदौर लाया जा रहा था। आबकारी विभाग ने मौके से वाहन चालक सूरज पिता चिमन बुन्देला, निवासी रंगवासा राऊ हाल मुकाम बाणगंगा, जिला इंदौर को गिरफ्तार किया।

कलेक्टर की पहल पर ग्रामीणों को मिली त्वरित राहत, ग्राम बदरखा में खुलवाया गया रास्ता

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर तहसील हातोद के ग्राम बदरखा में ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निराकरण करते हुए बंद रास्ते को खुलवाया गया। ग्रामीणों द्वारा मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में रास्ता बंद होने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और लैंडमार्क लाइब्रेरी को लेकर भी बैठक में हुए बड़े फैसले

इंदौर स्मार्ट सिटी का मेगा ब्लूप्रिंट हुआ तैयार

452 करोड़ की बनेगी ग्रीन टाउनशिप

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की 38वीं बोर्ड बैठक में शहर के भविष्य को बदलने वाले कई बड़े और महत्वाकांक्षी फैसलों पर मुहर लगी। कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी चेयरमैन शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रीन टाउनशिप, स्मार्ट ट्रैफिक नेटवर्क, अत्याधुनिक पब्लिक लाइब्रेरी, पार्किंग प्रबंधन और अधोसंरचना विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं कार्यपालक निदेशक क्षितिज सिंघल, स्मार्ट सिटी सीईओ अर्थ जैन, इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और स्वतंत्र निदेशक मौजूद रहे।

452 करोड़ की ग्रीन टाउनशिप बनेगी– बैठक का सबसे बड़ा फैसला एमओजी लाइन पुनर्विकास परियोजना को लेकर रहा। मऊ नाका स्थित ओल्ड गवर्नमेंट क्वार्टर्स क्षेत्र में सड़क, सीवर, जलप्रदाय, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, अंडरग्राउंड जलाशय, 33/11 केवी सब-स्टेशन, अंडरग्राउंड केबलिंग और आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सुविधाओं के विकास को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लाइन पार्सल 2 के करीब 68,510 वर्गमीटर क्षेत्र में डीबीएफओएस मॉडल पर ग्रीन और क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव टाउनशिप विकसित करने की योजना को स्वीकृति दी गई। इस परियोजना का आरक्षित मूल्य लगभग 452 करोड़ रुपए तय किया गया है। स्मार्ट सिटी अधिकारियों के मुताबिक ये इंदौर की सबसे आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल टाउनशिप परियोजनाओं में शामिल होगी। बैठक में मेसर्स तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड को आवंटित एमओजी लाइन ब्लॉक 11 परियोजना की समीक्षा भी हुई। भुगतान दायित्वों और समयसीमा का पालन नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ अनुबंध के अनुसार कार्रवाई पर चर्चा की गई। इससे साफ संकेत मिले कि स्मार्ट सिटी अब परियोजनाओं में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है।

शहर में और मजबूत होगा स्मार्ट ट्रैफिक नेटवर्क–बैठक में शहर के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के विस्तार को भी मंजूरी मिली। अब शहर के अतिरिक्त इलाकों में भी हाईटेक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। यह कार्य पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल, निगरानी और सड़क सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। छप्पन दुकान क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और पार्किंग अव्यवस्था को देखते हुए दोपहिया पार्किंग संचालन और रखरखाव के लिए फिर से टेंडर जारी करने का फैसला लिया गया। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य इस फूड स्ट्रीट को अधिक पैदल यात्री अनुकूल बनाना है।

इंदौर को मिलेगी अत्याधुनिक लैंडमार्क लाइब्रेरी

बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में आधुनिक 'लैंडमार्क पब्लिक लाइब्रेरी' विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस हाईटेक लाइब्रेरी में डिजिटल रीडिंग जोन, आधुनिक अध्ययन सुविधाएं, कैफेटेरिया और मल्टीपर्पज स्पेस विकसित किए जाएंगे। साथ ही निविदा प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड में चर्चा हुई। स्मार्ट सिटी बोर्ड की इस बैठक को इंदौर के शहरी विकास, ट्रैफिक प्रबंधन और आधुनिक अधोसंरचना के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गर्मी में सूखने नहीं देंगे पौधे, हर वार्ड में बनेंगे आदर्श उद्यान

उद्यान विभाग प्रभारी ने दिए निर्देश, रोपेंगे पौधे

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए शहर के उद्यानों, ग्रीन बेल्ट और सेंट्रल डिवाइडरों के रखरखाव को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनकार्य एवं उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर ने उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को हरित क्षेत्रों के बेहतर रखरखाव और सिचाई व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राठौर ने शहर में विकसित किए जा रहे नए सेंट्रल डिवाइडरों में पौधरोपण एवं उनके नियमित रखरखाव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

पौधरोपण के लिए स्थान चिह्नित करें : राठौर

उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने की तैयारी अभी से शुरू करने को कहा। इसके लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने तथा चयनित संस्थाओं के माध्यम से उद्यानों, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल डिवाइडरों एवं रोटरी के रखरखाव कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

आदर्श उद्यानों की प्रगति की भी समीक्षा की

बैठक में प्रत्येक वार्ड में विकसित किए जा रहे आदर्श उद्यानों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। राठौर ने चयनित उद्यानों में ओपन जिम, बेंच, झूले और चकरी जैसी सुविधाएं विकसित करने पर जोर देते हुए कहा कि उद्यानों को बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक उपयोगी एवं आकर्षक बनाया जाए।

पौधों की उपलब्धता निश्चित करें

नर्सरियों में पौधों की उपलब्धता, नियमित आपूर्ति, रखरखाव में उपयोग होने वाले संसाधनों एवं वाहनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। ग्रीष्म ऋतु में पौधों और वृक्षों की सिचाई प्रभावित न हो, इसके लिए पर्याप्त जल टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

मेट्रो में मैनुअल टिकटिंग से चला रहे अभी भी काम

मेट्रो में ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम तैयार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● यात्रियों को अभी ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम का इंतजार करना पड़ेगा। बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा में तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, किंतु यात्रियों को अभी भी ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम का इंतजार करना पड़ेगा। इंदौर मेट्रो के पांच स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन (एएफसी) सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, फिर भी मैनुअल टिकटिंग से ही काम चलाया जा रहा है। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक इस सिस्टम का शुभारंभ अब सुपर कॉरिडोर से विजयनगर के बीच मेट्रो के कमर्शियल रन के साथ ही किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार प्रबंधन को शासन की ओर से निर्देश मिले हैं कि पब्लिक रन के लिए पूरी तैयारी रखी जाए।

संकेत मिले हैं कि पीएमओ स्तर पर तारीख तय करने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलेगी, इंदौर वासियों को मेट्रो के आधुनिक और हाईटेक सफर का अनुभव मिलेगा। इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसे पब्लिक ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया गया है।

शहर के अनेक स्थानों पर स्वच्छता के नए-नए कैनवास बना रहा है निगम

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● स्वच्छ शहर अब सार्वजनिक स्थानों को एक विशाल खुली गैलरी में बदलकर अपनी शहरी सुंदरता को और निखार रहा है। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के तहत शहर भर में एक व्यापक थीम-आधारित सौंदर्यीकरण अभियान शुरू किया है। अतिरिक्त आयुक्त सिंह ने टीओआई को बताया, 'नगर निकाय वर्तमान में एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है जिसमें लगभग 10,000 मीटर की दीवार पेंटिंग और 50,000 मीटर की दीवार लेखन शामिल है।'

उन्होंने कहा कि यह पहल केवल सजावट से कहीं अधिक है; कलाकार धूल भरी धूसर दीवारों, विभाजकों, फ्लाईओवरों और सार्वजनिक संरचनाओं में जीवंत रंगों और जटिल भित्ति चित्रों से जान डाल रहे हैं। यह परियोजना 'दृश्य स्वच्छता' को बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई है। आईएमसी इस 'सबसे बड़े कैनवास' का उपयोग सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। शहर भर में दीवारों पर लिखे संदेशों में कचरा पृथक्करण, एकल-उपयोग प्लास्टिक के खतरों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और पेशाब करने से होने वाले 'लाल धब्बे' और 'पीले धब्बे' की रोकथाम के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। शहर को एक समान और स्वच्छ बनाए रखने के लिए, निगम प्रमुख सड़कों पर पारंपरिक चूने और गेरू का उपयोग करके वृक्षों को रंग रहा है। सिंह ने कहा कि प्राथमिक उद्देश्य कला को पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी के साथ जोड़कर इंदौर की स्वच्छता परंपरा को मजबूत करना है। आईएमसी ने नागरिकों से सौंदर्यीकरण प्रयासों की रक्षा करने और शहर की दीवारों को अनधिकृत पोस्टरों या दागों से मुक्त रखने में सहयोग करने की अपील की है।

पालदा में नए बिजली सब स्टेशन की जमीन का निरीक्षण

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शहर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली वितरण क्षमता का विस्तार किया गया रहा है, ट्रांसफार्मर, केबल, कंडक्टर भी अत्याधुनिक स्तर के लगाए जा रहे है। शहर के पालदा औद्योगिक क्षेत्र में नया 33/11 केवी सब स्टेशन तैयार किया जाना है। इसकी जमीन का निरीक्षण करने के लिए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युय वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने मंगलवार दोपहर दौरा किया। उन्होंने करीब ढ़ाई करोड़ की लागत से बनने वाले 5 एमवीए क्षमता के 33/11 केवी नए ग्रिड के निर्माण स्थल पर सिविल का कार्य जल्दी करने के निर्देश दिए। सिंह ने पालदा का पुराना ग्रिड भी देखा, पालदा औद्योगिक क्षेत्र की मौजूदा बिजली वितरण व्यवस्था एवं शिकायत निवारण इत्यादि की जानकारी ली। सिंह ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्षेत्र की बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय हैं क्यों कि इससे विकास, रोजगार का सीधा संबंध होता है।

इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला पर सुनवाई पूरी, अब फैसले का इंतजार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर/धार ● धार भोजशाला पर मंगलवार 12 मई को सुनवाई पूरी हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई चल रही थी। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने पूरी सुनवाई की। इसमें शासन पक्ष की ओर से एजी प्रशांत सिंह ने तो वहीं हिंदू पक्ष की ओर से मुख्य याचिकाकर्ता आशीष गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन, अधिवक्ता विनय जोशी, पार्थ यादव आदि ने बात रखी। एएसआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता व एडिशनल सालिसिटर जनरल सुनील जैन थे।

इन अधिवक्ताओं ने भी रखे तर्क

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, अजहर वारसी, नूर अहमद थे, तो एक अन्य याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन थी। एक अन्य याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एके चितले व कार्तिक चितले थे।

हिंदू फ्रंट की ओर से लगी थी याचिका

साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री एवं उनके साथियों द्वारा याचिका दायर हुई थी। इंदौर उच्च न्यायालय में भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय कर हिंदू समाज के पूर्ण आधिपत्य के लिए याचिका

क्रमांक 10497/ 2022 लगाई गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए और वहां 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे हुआ।

फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वहां से हाईकोर्ट को केस की सुनवाई तय समय में करने के लिए कहा गया। इसके बाद सभी याचिकाएं लिंक करके सभी को सुना गया। इसमें जैन समाज ने भी याचिका दायर की ओर कहा कि यह जैन मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद है।

हिंदू पक्ष की ओर से तर्क और मांग

हिंदू समाज की मांग है कि भोजशाला में अनुच्छेद 25 के अनुसार पूजा का अधिकार मिले तथा मुस्लिम समाज को भोजशाला परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाए। केंद्र सरकार को आदेशित किया जाए कि भोजशाला के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए जिससे कि भोजशाला का संचालन एवं प्रबंध किया जा सके।

ट्रस्ट को यह आदेशित किया जावे कि मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा एवं अर्चना निर्बाध रूप से कराई जाए। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही नमाज बंद हो। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को निरस्त किया जाए एवं हिंदू समाज को नियमित प्रतिदिन पूजा करने का अधिकार मिले। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी माँ वाग्देवी की प्रतिमा को पुन: वापस लाया जावे एवं भोजशाला धार में स्थापित किया जाए।

मुस्लिम पक्ष का दावा

वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद है। साल 1935 से यह वक्फ संपत्ति है। यदि मंदिर होता तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। कैरेक्टर तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। यहां पर वरशिप एक्ट लागू नहीं होता है। वैज्ञानिक सर्वे में कार्बन डेटिंग का उपयोग नहीं हुआ ऐसे में तय नहीं कि यह परमारकालीन निर्माण है। पूरा सर्वे गलत है। यह सिविल वाद है और कायदे से इसकी सुनवाई जिला कोर्ट में होना चाहिए इसलिए याचिका ही मेंटेनेबल नहीं है। जो प्रतिमा वाग्देवी की बताई जा रही है वह इस परिसर में मिली ही नहीं थी।

सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की मांग

उधर अन्य याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि फैसला कुछ भी हो लेकिन ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएं कि यहां पर सौहार्द माहौल बना रहे। बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात संविधान की है और कानून व्यवस्था की है। ऐसे में इस तरह के दिशा निर्देश तय किए जाएं कि फिर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, बुधवार 13 मई 2026

न्यूज ब्रीफ

श्री सिद्ध हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू, जल्द लगेगी आकर्षक रोशनी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● हुजरगंज श्री सिद्ध हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया। जल समस्या को देखते हुए बोरिंग तथा मंदिर परिसर के चारों ओर स्ट्रीट लाइट लगाने की स्वीकृति पार्षद शिखा संदीप दुबे द्वारा दी गई। इसको लेकर आयोजित बैठक में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाएगा। सुमित अवस्थी ने बताया कि बोरिंग और स्ट्रीट लाइट की स्वीकृति मिलने से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी तथा मंदिर परिसर में सुविधाएं और बेहतर हो सकेंगी। बैठक में मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं और क्षेत्रीय विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई।

विधर्मी और विदेशी ताकतों से सतर्क रहकर सशक्त, संगठित और निरंतर प्रतिरोध करें -प्रहलाद मोदी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● वर्ल्ड हिन्दू फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुज प्रहलाद दामोदरदास मोदी ने कहा है कि सनातन धर्म हमारी सबसे बड़ी पहचान, शक्ति और रक्षाकवच है। विडम्बना है कि आज कुछ विधर्मी और विदेशी ताकतें खुलेआम सनातन धर्म पर आक्रमण कर हमारे देवी-देवताओं का अपमान भी कर रही हैं और हमारे मंदिरों पर कब्जा करने से लेकर हिन्दू समाज को विभाजित करने के दुष्प्रयासों में भी जुटी हुई हैं। हमारे त्योहारों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क रहकर सशक्त, संगठित और निरंतर प्रतिरोध करने की जरूरत है। मोदी ने यह बात अपने इंदौर, बडवाह, ओंकारेश्वर और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर दर्शन, पूजन एवं फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं से मुलाकात एवं संबोधन के दौरान कही। फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि मोदी ने सोमवार-मंगलवार को प्रदेश महामंत्री रोहित मित्तल, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता विनोद जायसवाल, बड़वाह इकाई के अध्यक्ष रवि जैन एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ अंचल का दौरा किया। मोदी का ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में पुष्पमाला, तिलक एवं सनातनी संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया गया, वहीं महाकालेश्वर में भी उन्हें भगवान महाकाल की तस्वीर एवं प्रसाद भेंटकर सम्मानित किया गया।

आज अचला एकादशी पर साजन नगर के खाटू श्याम मंदिर में अखंड ज्योत

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● नवलखा स्थित साजन नगर में खाटू श्याम एवं नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर अचला एकादशी महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार 13 मई को विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मंदिर प्रबंध समिति के प्रमुख सुरेश रामपीपलिया एवं साजन नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष सुजीत शर्मा ने बताया कि शाम 7 बजे से श्याम बाबा की दिव्य ज्योत, भव्य श्रृंगार एवं भजन संकीर्तन के पश्चात प्रथम एक हजार भक्तों को बरकती सिक्के बांटें जाएँगे। आयोजन से जुड़े प्रहलाद गोयल, राहुल व्यास एवं अतुल अग्रवाल चाय ने बताया कि मंदिर पर शाम 7 बजे से भजन गायक पियूष भावसार और उनकी टीम द्वारा मनोहारी भजन संकीर्तन की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।

वीआईपी काफिलों पर ब्रेक, मुख्यमंत्री घटाएंगे गाड़ियां, 13 की जगह 8 वाहन होंगे

भोपाल (एजेंसी) ● प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करने की अपील के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब मंत्रियों और वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित की जाएगी। साथ ही सरकारी दौरों और भ्रमण के दौरान रैलियों पर भी रोक रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जेड+ सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है। इसी वजह से उनके काफिले में अब तक कुल 13 वाहन शामिल रहते थे। नए आदेश के बाद भोपाल में स्थानीय भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले में अब सिर्फ 8 वाहन शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- राष्ट्रहित में ईंधन की खपत कम करना समय की जरूरत है। इसकी शुरुआत सरकार खुद करेगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि नवनियुक्त निगम-मंडल पदाधिकारी सादगी के साथ कार्यभार ग्रहण करेंगे। ईंधन बचत सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वहीं मंगलवार को भोपाल में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के नवनियुक्त

अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह ई-रिक्शा से पदभार ग्रहण करने पहुंचे। हालांकि, उनके साथ समर्थकों का कार और बाइक काफिला भी नजर आया। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन भी ई-रिक्शा से भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ तीन लोगों के साथ आए थे, बाकी लोग किस वाहन से पहुंचे इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ई-स्कूटी से मंत्रालय पहुंचे।

वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल भी करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर हाई कोर्ट पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा- यह सोच गलत है कि हाई कोर्ट के जज साइकिल से नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो, सभी लोगों को साइकिल चलाकर पेट्रोल-डीजल की बचत करना चाहिए। उन्होंने इसे पर्यावरण और देशहित से जुड़ा विषय बताया। वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा से प्रेरित होकर साइकिल चला रहे हैं। इस दौरान हाई कोर्ट के कुछ कर्मचारियों ने भी बैग और टिफिन लेकर साइकिल से आने-जाने की पहल की।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल के शिवाजी नगर स्थित अपने सरकारी आवास से ई स्कूटी के जरिए पहुंचे। लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण के पदभार ग्रहण में शामिल हुए। इसके बाद वे ई स्कूटी से ही मंत्रालय पहुंचे।

अच्छी बिजली के लिए अनोखा जतन....

भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर के अर्थिंग के लिए दे रहे पानी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भरी गर्मी में आखिर कौन परेशान नहीं हैं, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी.... यहीं नहीं बिजली के संसाधनों को भी गर्मी से परेशानी होती है, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है, ताकि शहर के उपभोक्ताओं को बिजली मिलती रहे, गर्मी से निजात के लिए कूलर, पंखे, एयरकंडीशनर, फ्रीज इत्यादि चलते रहे। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। शहर में करीब तेरह हजार ट्रांसफार्मरों से बिजली आपूर्ति होती है। शहर में हमारे घर, गली, बहुमंजिला इमारत, मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, चौराहे के पास ट्रांसफार्मर आसानी से देखे जा सकते हैं, शहर में इस तरह के ट्रांसफार्मर जिसे आम बोली में डीपी कहा जाता हैं, इन्हें भीषण गर्मी में सुचारू बनाए रखने के लिए खास प्रयास किए जा रहे है। प्रत्येक ट्रांसफार्मर जो प्राय: चार खंभों पर लगा होता है, उसके नीचे अर्थिंग का प्रबंध किया जाता है। यह अर्थिंग उसी तरह कार्य करता हैं, जिस तरह मनुष्य को काढ़ा, हल्दी या नीम इत्यादि व्याधियों से बचाते हैं, स्वस्थ रखने मे मदद करते हैं। न्यूट्रल को अर्थ मिलने से आशय हैं ट्रांसफार्मर या आम लोगों की लाइनों के वोल्टेज , घरों में यदि कोई परेशानी आती हैं तो अर्थ मिलने का कारण ट्रांसफार्मर, एलटी लाईन या उपभोक्ताओं के बिजली उपकरणों को नुकसानी से बचाया जा सकता हैं। गर्मी में जब जमीन से पानी पूरी तरह सुख जाता हैं, तो ट्रांसफार्मर मे अर्थिंग वाले स्थान को नमीयुक्त बनाए रखने बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसीलिए शहर में जोन कर्मचारी ट्रांसफार्मर के पास यदि कही पानी हो तो वहां से लेकर या चार पहिया वाहन में एक टंकी रखकर पाइप की मदद से ट्रांसफार्मर के अर्थिंग वाले स्थान पर पानी डाल रहे हैं। इससे जहां भीषण गर्मी में आपूर्ति अनवरत बनाए रखने में मदद मिल रही हैं, वहीं ट्रांसफार्मर को किसी नुकासानी से भी बचाने में कामयाबी मिल रही हैं, ट्रिपिंग में कमी भी लाई जा रही है। बिजली कंपनी के इंदौर शहर वृत्त अधीक्षण अभियंता श्री डीके गाठे बताते हैं कि जोन के कर्मचारियों ने जरूरत होने एवं जहां लोड की अधिकता की संभावना हैं वहां प्राथमिकता से पानी डालने के कार्य को नियमित रूप से किया है। फ्यूज सुधारने के वाहन में टंकी भरकर रखी जाती है, बिजली सुधार के बाद वापस लौटते समय लाइनकर्मी जरूरत के मुताबिक ट्रांसफार्मर के अर्थिंग में पानी डालकर लौटते हैं, ताकि समय की बचत होती है।

मोदी छाप ताले लेकर कांग्रेस सेवादल पहुँचा सराफा बाजार

व्यापारियों ने कहा - सरकार हमारे कारोबार पर ताला लगाने पर उतारू

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद इंदौर के सराफा व्यापारियों में भारी नाराज़गी और चिंता का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर आज इंदौर जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, मधुसूदन भालकी,गिरीश जोशी, आकाश निजामपुरकर,दीपक नागा के नेतृत्व में कांग्रेसजनों का प्रतिनिधिमंडल सराफा बाजार पहुँचा, जहाँ व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा सुनी गई और सांकेतिक रूप से 'मोदी छाप ताले' के पोस्टर भेंट किए गए।

इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने व्यापारियों से कहा कि देश पहले ही आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और बाजार में घटती खरीद क्षमता से जूझ रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का यह बयान सराफा व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार व्यापार बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोगों को

रोजगार देने वाले व्यापार को बंद करने जैसे बयान देकर बाजार में भय और अस्थिरता पैदा कर रही है। खंडेलवाल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि -

'नोटबंदी, गलत जीएसटी और लगातार आर्थिक अव्यवस्था के बाद अब सराफा व्यापार पर 'मोदी छाप ताला' लगाने की तैयारी की जा रही है। यह सिर्फ व्यापारियों पर हमला नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों पर चोट है जिनकी रोजी-रोटी इस व्यवसाय से चलती है। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से मधुसूदन भालकी, गिरीश जोशी, दीपक नागा सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। सभी ने सराफा बाजार में व्यापारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएँ सुनीं।

इंदौर के बहुचर्चित हत्या प्रकरण में तीनों आरोपी बरी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● वर्ष 2022 के चर्चित हत्या प्रकरण में इंदौर के अपर सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों से तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील अहीरवार की अदालत ने 11 मई 2026 को यह निर्णय सुनाया। मामले में आरोपी अब्दुल मजीद उर्फ मज्जू, गुलनाज उर्फ गुलफ्शा और नसीम बी पर धारा 302, 307 एवं 34 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन के अनुसार 12 अक्टूबर 2022 को पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी पति-पत्नी और बेटियों ने अब्दुल हमीद की डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी गई थी तथा उसकी पत्नी अनीसा को पहली मंजिल से नीचे फेंककर घायल किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के कई गवाहों के बयान परस्पर विरोधाभासी रहे। जबकि कई महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि न्यायालय में स्पष्ट रूप से नहीं हो सकी।

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ दिल्ली की इंदौर जिला कार्यकारिणी घोषित; विनोद शर्मा बने जिलाध्यक्ष

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ (नई दिल्ली) की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा इंदौर जिले की कार्यकारिणी की घोषणा शुक्रवार को की गई। पिपलियाराव रोड स्थित मधुर मिलन गार्डन में आयोजित भव्य समारोह में जिले के साथ-साथ तहसीलों के पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। नवनियुक्त टीम ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कर पदभार संभाला।

वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण- कार्यक्रम में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष- उपेंद्र गौतम, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष- सत्यनारायण वैष्णव व अरविंद द्विवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री राहुल सिंह राणा, प्रदेश महासचिव रामगोपाल बंसल और प्रदेश सचिव जुनैद खान विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान शहडोल जिलाध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, विदिशा जिलाध्यक्ष हाकिम सिंह रघुवंशी, महासचिव योगेश पंथी सहित एडवोकेट जगदीश जोशी, एडवोकेट विजय कुमावत और सुशील श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

देवास में मछलियों को बचाने तालाब में छोड़ा गया पानी, भीषण गर्मी से ऑक्सीजन घटने लगी थी

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● भीषण गर्मी के बीच नगर निगम ने सयाजी द्वार के सामने स्थित पुष्कर मंडूक तालाब में मछलियों के संरक्षण के लिए पानी डाला। मंगलवार दोपहर की गई इस कवायद का उद्देश्य गर्मी और पानी के ठहराव के कारण मछलियों के मरने की आशंका को कम करना था। नगर निगम की टीम ने दो दमकल गाड़ियों का उपयोग कर तालाब में पानी भरा। इसके साथ ही, पानी को ऑक्सीजन युक्त करने की प्रक्रिया भी की गई, ताकि मछलियों के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, तालाब के पानी के अत्यधिक गर्म होने और उसमें ठहराव बढ़ने से मछलियों पर खतरे की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के मद्देनजर निगम की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। नगर निगम अधिकारी जितेंद्र सिसोदिया ने बताया कि गर्मी के कारण तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका थी, जिससे मछलियों की मौत हो सकती थी। इसे देखते हुए पानी को ऑक्सीजन युक्त किया गया और अतिरिक्त पानी डाला गया।

नर्मदा-क्षिप्रा योजना बंद होने से गांवों में जल संकट गहराया

दैनिक इंदौर संकेत

देवास ● नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना के तहत देवास के उदयनगर के समीप सबलगढ़ गांव में स्थित पंप स्टेशन और मुहाडा घाट क्षेत्र में पिछले तीन माह से पानी की आपूर्ति बंद है। इसके कारण ग्रामीणों, किसानों और वन्यजीवों के सामने गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। इस समस्या को लेकर सीतावन उत्थान सेवा समिति और स्थानीय ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने योजना से जलप्रदाय पुन: शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि नर्मदा-क्षिप्रा योजना के अंतर्गत सबलगढ़ नाले और लोहाड नदी में दो स्थानों पर पानी छोड़ा जाता था। पिछले दो वर्षों से इस पानी से आसपास के क्षेत्रों में जल उपलब्धता बनी हुई थी। यह पानी जंगल के वन्यजीवों और ग्रामीणों के पालतू पशुओं की प्यास बुझाने के साथ-साथ 5 से 6 गांवों के किसानों को सीमित सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होता था, जिससे उनका जीवनयापन होता था। हालांकि, विगत तीन माह से इन दोनों स्थानों पर पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई का संकट गहरा गया है। ग्रामीणों के अनुसार, जलस्तर में

लगातार गिरावट आ रही है, जिसके चलते तहसील मुख्यालय उदयनगर सहित इमलीपुरा और रामपुरा जैसे क्षेत्रों में भी पानी की समस्या बढ़ गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि नर्मदा-क्षिप्रा योजना के तहत पानी की आपूर्ति तत्काल बहाल की जाए, ताकि वन्यजीवों, पशुओं और किसानों को राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सबलगढ़ स्टेशन से उदयनगर क्षेत्र के लिए पेयजल पाइपलाइन स्वीकृत करने की भी मांग की है।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

प्रवेश परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियों के मामले सामने क्यों आ रहे हैं?

नीट परीक्षा जरूरी है कि प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। देश भर में हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मगर उनकी उम्मीदें तब धुंधली पड़ जाती हैं, जब परीक्षा में अनियमितता की बातें सामने आती हैं या फिर पर्चाफोड़ की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस बार भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026 'में पर्चाफोड़ के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई है। सवाल है कि इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियों के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? एनटीए का दावा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसे संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में पूरी गोपनीयता बरती जाती है और जरूरी सुरक्षा मानदंडों का भी कड़ाई से पालन किया जाता है, फिर क्या वजह है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र चुनिंदा विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है! आखिर एनटीए और जांच एजंसियां उस सिरे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह की गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि उन्हें दूसरी भाषा के प्रश्नपत्र दिए गए। इसके बाद एनटीए की ओर से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रभावित परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे। इससे पहले वर्ष 2021 में भी कुछ छात्रों को गलत प्रश्नपत्र दिए जाने और कई केंद्रों पर परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतों से विवाद हुआ था। सरकार ने वर्ष 2018 में एनटीए की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करना है, जिनमें नीट, जेईई, यूजीसी और नेट भी शामिल हैं। दरअसल, प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष बनाना एनटीए की बुनियादी प्राथमिकता है।

कौन जवाब देगा नीट की इस लगातार बिगड़ती व्यवस्था का?

कड़े नियमों, डिजिटल निगरानी और सुधार के दावों के बावजूद जब परीक्षा व्यवस्था बार-बार संदेह में आ जाए, तो नीट-यूजी 2026 जैसी घटनाएँ पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देती हैं। 3 मई को देशभर के 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ परीक्षा दी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह विवादों में घिर गई। 12 मई को एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। राजस्थान एसओजी की प्रारंभिक जांच में 'गेस पेपर' और प्रश्नों के मेल ने परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर चोट पहुँचाई। यह केवल परीक्षा रद्द होने की घटना नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र की गहरी संरचनात्मक विफलताओं का स्पष्ट संकेत बन गई। जब लाखों विद्यार्थी किसी परीक्षा के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष समर्पित करते हैं, तो उनका पूरा भविष्य उसी एक दिन से जुड़ जाता है। नीट अभ्यर्थियों ने कोचिंग, टेस्ट सीरीज, निरंतर अभ्यास और मानसिक दबाव के बीच कठिन संघर्ष किया, लेकिन परीक्षा रद्द होने के फैसले ने उनकी मेहनत को अनिश्चितता में धकेल दिया। ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्रों पर भी इसका गहरा असर पड़ा, जो सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके लिए यह परीक्षा केवल प्रवेश नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति का अवसर थी, जो फिर से अधर में लटक गया।

जब किसी बच्चे के सपने को साकार करने के लिए परिवार अपनी पूरी जमा-पूंजी, कर्ज और संसाधन तक दाँव पर लगा देता है, तब ऐसा निर्णय उन्हें आर्थिक ही नहीं, गहरे मानसिक आघात से भी जकड़ देता है। मध्यमवर्गीय माता-पिता ने कोचिंग, हॉस्टल, किताबों और तैयारी पर अपनी सीमाओं से बाहर जाकर खर्च किया था। परीक्षा रद्द होने से यह निवेश अब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भावनात्मक टूटन में बदल गया है। कई घरों में तनाव और चिंता बढ़ गई है। माता-पिता के मन में अब यही सवाल गूंज रहा है कि क्या हर साल उनके बच्चों का भविष्य इसी तरह अनिश्चितता के अंधेरे में फँसा रहेगा?

मल्टी-लेयर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, फ्लाइंग स्क्वाड और सीलबंद प्रोटोकॉल जैसी मजबूत व्यवस्थाओं के बावजूद जब बार-बार पेपर लीक और प्रश्नों के मिलान जैसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो यह परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। राजस्थान के सीकर जैसे कोचिंग केंद्र में उजागर हुआ 'गेस पेपर' का

मामला यह दिखाता है कि समस्या केवल परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की श्रृंखला में कहीं गहराई तक फैली हो सकती है। प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर भंडारण, परिवहन और वितरण तक हर चरण में यदि थोड़ी भी चूक रह जाए, तो पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सीधा असर पड़ता है। गलती सामने आने पर हर बार परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं, बल्कि उसका सीधा बोझ छात्रों पर डाल देना बन जाता है, जबकि वास्तविक चूक करने वाली व्यवस्था अक्सर जवाबदेही से बच जाती है। यही सबसे बड़ा असंतुलन है। सिस्टम की खामियों को सुधारने के बजाय उसकी कीमत अभ्यर्थियों को समय, श्रम और मानसिक दबाव के रूप में चुकानी पड़ती है। यह सिलसिला बार-बार दोहराया जाता है, लेकिन जवाबदेही का स्पष्ट ढांचा आज भी कमजोर प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल और भी तीखा हो जाता है कि जब सुरक्षा के इतने स्तर मौजूद हैं, तो आखिर चूक किस चरण में और किसकी लापरवाही से हो रही है?

एनटीए द्वारा यह कहना कि छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा और फीस वापस कर दी जाएगी, केवल एक औपचारिक प्रशासनिक घोषणा प्रतीत होती है, जबकि मूल संकट जस का तस बना हुआ है। नई परीक्षा तिथि को लेकर बनी अनिश्चितता ने पूरे मेडिकल प्रवेश कैलेंडर को अस्त-व्यस्त कर दिया है। एमबीबीएस व अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों के सत्र में संभावित देरी का प्रभाव किसी एक बैच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। हर टलती तारीख का अर्थ छात्रों के जीवन में समय, अवसर और भविष्य का लगातार पीछे खिसकना है।

जब किसी एक परीक्षा पर उठे सवाल पूरे चिकित्सा शिक्षा ढांचे की साख को हिला दें, तो यह केवल शैक्षणिक मुद्दा नहीं, बल्कि सिस्टम की गहरी विफलता बन जाता है। एआईआईएमएस, जेआईपीएमईआर जैसे शीर्ष संस्थानों में प्रवेश नीट पर निर्भर है, और उसी परीक्षा की पारदर्शिता संदिग्ध हो जाए, तो पूरा मेडिकल भविष्य अस्थिर हो जाता है। छात्रों का असंतोष अब केवल भावनात्मक नहीं रहा, बल्कि एक संगठित और निर्णायक मांग में बदल चुका है—कड़ी सुरक्षा, वास्तविक डिजिटल पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था की।

सीबीआई जांच की घोषणा ने भले ही उम्मीद जगाई हो कि दोषियों तक पहुंच संभव होगी, लेकिन केवल जांच अपने आप में समस्या का समाधान नहीं बन सकती। असली आवश्यकता गहरे प्रणालीगत सुधारों की है—जो केवल तकनीक तक सीमित न होकर प्रशासनिक ढांचे और संरचना दोनों को मजबूत करें। यदि स्पष्ट और कठोर जवाबदेही तय नहीं की गई, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना कठिन होगा। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमित निगरानी और सख्त ऑडिट प्रणाली अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है।

जब एक ही परीक्षा 22 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य का निर्णायक आधार बन जाए और वही बार-बार विवादों के घेरे में फँसती रहे, तो यह केवल शैक्षणिक असफलता नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिभा के क्षरण का गंभीर संकेत है। हर बार छात्रों का समय, परिश्रम और मानसिक ऊर्जा दांव पर लगती है, जबकि व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। यह स्थिति अब सामान्य चिंता नहीं, बल्कि स्पष्ट चेतावनी बन चुकी है कि यदि तुरंत ठोस और निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह टूट सकता है।

बार-बार सामने आने वाली यह स्थिति अब एक गंभीर प्रश्न बन चुकी है कि क्या छात्र हमेशा परीक्षा की अनिश्चितता, रद्दीकरण और दोबारा तैयारी के बोझ में ही उलझे रहेंगे। इसका उत्तर किसी जांच या औपचारिक आश्वासन से नहीं निकल सकता। जरूरत ऐसी मजबूत और जवाबदेह व्यवस्था की है जहाँ त्रुटियों की संभावना कम हो और हर स्तर पर जिम्मेदारी स्पष्ट हो। तभी लाखों छात्रों के सपनों को व्यवस्था की चूक से बचाया जा सकेगा और उनका भविष्य सुरक्षित, पारदर्शी तथा स्थिर दिशा में आगे बढ़ सकेगा—वरना भरोसे का यह संकट और गहरा होगा और सबसे बड़ी कीमत प्रतिभा को चुकानी पड़ेगी।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'
शिक्षाविद्, बड़वानी (मप्र)

एक साल में 16831 अधूरी कहानियां

अखबारों के पिछले पन्नों पर एक छोटे-से कॉलम में छपा यह आंकड़ा शायद आपने भी पढ़ा होगा... मध्यप्रदेश में एक वर्ष में 16,831 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर गए। ज़रा ठहरकर सोचिए... यह सिर्फ एक भर आंकड़ा नहीं है। यह 16,831 अधूरी कहानियाँ हैं। 16,831 घरों के बुझ चुके चूल्हे हैं। 16,831 बच्चों के सिर से उठ चुका पिता का हाथ है ।16,831 माताओं की सूनी आँखें हैं जो आज भी दरवाज़े की आहट पर चौंक जाती हैं। 16,831 पत्नियों की टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। 16,831 परिवार हैं जो सुबह तक 'सामान्य' थे... और शाम होते-होते बर्बाद हो गए। और सबसे भयावह बात क्या है जानते हैं? इनमें से केवल 15 मौतें खराब सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दर्ज हुईं। बाकी लगभग सारी मौतें... हमारी जल्दबाज़ी, लापरवाही, अहंकार और हठधर्मिता ने लीं। हाँ... वही हठधर्मिता जो कहती है, 'अरे कुछ नहीं होता...' 'सब चलता है...' 'पहले सबको सुधारो फिर हमें बोलना...' 'हेलमेट से क्या फर्क पड़ता है...' 'बस दो मिनट की तो बात है...'

लेकिन यही 'दो मिनट' किसी बच्चे से उसका पिता छीन लेते हैं। यही 'कुछ नहीं होता' किसी माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी कर देता है। यही 'सब चलता है' किसी घर की साँसें रोक देता है।

हम लाल बत्ती तोड़ते हैं जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। हम गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं जैसे बहुत चतुर हों। हम बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट सड़कों पर ऐसे निकलते हैं मानो मौत से दोस्ती कर ली हो। और समाज? हमारे करतबों पर वह भी ताली बजाता है। नियम तोड़ने वाले को 'स्मार्ट' कहता है। कानून मानने वाले को 'डरपोक' समझता है। लेकिन सड़क पर जब किसी युवक का सिर फटकर डामर पर बिखरता है... जब किसी माँ का कलेजा अस्पताल के बाहर चीख-चीखकर फटता है... जब कोई पाँच साल का बच्चा पूछता है, 'मम्मी, पापा अब कभी नहीं आएँगे क्या...?' तब न 'स्मार्टनेस' बचती है...न 'जल्दी '...न 'स्टेटस '...न 'ईगो '...बचता हैं तो सिर्फ, एक ऐसा दर्द... जो जीवनभर खत्म नहीं होता।

देश में हर घंटे 20 लोग सड़क पर मर रहे हैं। मध्यप्रदेश में हर दिन 46 लोग। कल्पना कीजिए... हर दिन 46 घरों में मातम उतरता है। 46 घरों में खाना नहीं बनता। 46 परिवारों की दुनिया उजड़ जाती है। लेकिन विडंबना देखिए फिर भी हम विचलित नहीं होते।

क्या सचमुच हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं? क्यों कोई धर्मगुरु मंच से यह नहीं कहता कि 'सुरक्षा नियम अपनाना भी धर्म है, क्योंकि जीवन बचाना सबसे बड़ा धर्म है '? क्यों कोई राजनेता अपने समर्थकों से यह नहीं कहता कि 'मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नियम मानो '? क्यों माता-पिता बच्चों के सामने खुद नियम तोड़ते हैं? क्यों स्कूल बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल का अर्थ नहीं सिखाते? क्यों हम घायल को सड़क पर तड़पता छोड़ वीडियो बनाते हैं?

राजकुमार जैन, यातायात प्रबन्धन विशेषज्ञ

आंचलिक

धार-महू के 36 स्कूलों को 142 करोड़ की सौगात, जनजातीय अंचलों में भवन, लैब और अतिरिक्त कक्ष बनेंगे

दैनिक इंदौर संकेत

धार ●धार-महू लोकसभा क्षेत्र के जनजातीय अंचलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 142 करोड़ 65 लाख 36 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि क्षेत्र के 36 हाई स्कूलों में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए है। सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के प्रयासों से यह सौगात मिली है। यह राशि मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी की गई है। स्वीकृत राशि से लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों का अधोसंरचना विकास किया जाएगा। इनमें धार विधानसभा के 7, गंधवानी के 6, सरदारपुर के 6, कुक्षी के 9 और मनावर विधानसभा क्षेत्र के 8 हाई स्कूल शामिल हैं। इन विद्यालयों में भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यक सुविधाएं और अन्य आधारभूत विकास कार्य कराए जाएंगे। इन विकास कार्यों से विशेष रूप से आदिवासी अंचलों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं मिलेंगी। लंबे समय से कई स्कूलों में भवन, अतिरिक्त कक्ष और अन्य संसाधनों की आवश्यकता थी, जिसे अब इस स्वीकृत राशि से पूरा किया जाएगा। सांसद सावित्री ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे और शिक्षा के माध्यम से हर वर्ग को सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेशभर में कई विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

किसान का घर आग से राख:सोयाबीन-चना जले, तीन बकरियों की मौत

दैनिक इंदौर संकेत

धार ●जिले के नालछा थाना क्षेत्र के ग्राम ढूंढी बयड़ी में मंगलवार को एक किसान के घर में आग लग गई। इस घटना में किसान का कच्चा मकान, सोयाबीन, चना सहित अन्य फसलें जलकर राख हो गईं। आग की चपेट में आने से मकान के पास बंधी तीन बकरियों की भी मौत हो गई। यह घटना गुलाब नामक किसान के घर में हुई। बताया गया कि अचानक मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की इस घटना में मकान के अंदर रखा सोयाबीन, चना और अन्य अनाज पूरी तरह जल गया। इसके अतिरिक्त, घर में रखे नकदी रुपए और सोने-चांदी के आभूषण भी आग में नष्ट हो गए। ग्रामीणों के अनुसार, किसान की सालभर की मेहनत कुछ ही देर में राख में बदल गई। ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

मांडू बना डिजिटल जनगणना में नंबर वन, एक सप्ताह में पूरा किया मकान सूचीकरण का लक्ष्य

दैनिक इंदौर संकेत

मांडू ● भारत सरकार की 16वीं और पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना के अभियान में मांडू नगर परिषद ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। 1 मई से 30 मई तक निर्धारित मकान सूचीकरण के कार्य को मांडू चार्ज कार्यालय ने एक सप्ताह में ही पूरा कर लिया है। इसी तरह दूसरे नंबर पर मनावर 61% और तीसरे नंबर पर गंधवानी 60% रहा। मंगलवार को मांडू के 15 वार्डों में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष 'जनगणना रथ' का संचालन किया जा रहा है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मांडू के 15 वार्डों को परिवार एवं जनसंख्या के आधार पर 22 गणना ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। कार्य की सुगमता के लिए 22 मुख्य प्रगणकों के साथ 3 रिजर्व प्रगणक और कार्यों के निरीक्षण हेतु 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। प्रगणक स्मार्टफोन और मोबाइल ऐप के माध्यम से घर-घर जाकर डेटा एकत्र कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिला जनगणना कार्यालय धार के मार्गदर्शन में संचालित 'जनगणना रथ' शहर के प्रमुख चौराहों और वार्डों में नागरिकों को जागरूक कर रहा है।

रथ पर स्थापित एलईडी पैनल के माध्यम से डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया और राष्ट्र निर्माण में सटीक डेटा के महत्व को प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील ठाकुर ने जनता से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महापर्व में सहयोग करें। इस बार नागरिक पोर्टल के माध्यम से 'स्व-गणना' भी कर सकते हैं। प्रथम चरण के दौरान घरों की सूची, आवास की स्थिति और उपलब्ध संपत्तियों जैसे पानी, बिजली व इंटरनेट का विवरण जुटाया जा रहा है।

गेहूं खरीदी केंद्र पर आगजनी, वेंटिलेशन से धुआं उठता दिखा फिर लपटें दिखी

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● छैगांवमाखन क्षेत्र में एक गेहूं खरीदी केंद्र पर आगजनी का मामला सामने आया है। आग की चपेट में आने से गेहूं की दर्जनों बोरियां जल गईं। किसानों ने धुआं उठता और आग की लपटें देखीं, जिसके बाद केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों को जानकारी दी। इसके बाद टैंकर से पानी लाकर आग बुझाई गई। मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था।

घटना ग्राम पछाया स्थित अष्टविनायक वेयरहाउस की है। यहां गेहूं खरीदी कर गोदाम क्षेत्र में गेहूं से भरी बोरियों की थप्पियां लगाकर स्टॉक किया गया था। इसी स्टॉक एरिया में आग लग गई। घटना के समय वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। वेयरहाउस के वेंटिलेशन से धुआं उठता दिखाई दिया। इसके बाद शटर खुलवाए गए तो अंदर आग की लपटें उठ रही थीं। हालांकि शटर लॉक नहीं थे।

आग अलग-अलग हिस्सों में लगी हुई थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी व्यक्ति ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अष्टविनायक वेयरहाउस के भीतर किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी नहीं थी, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं मानी जा रही। इसे किसी की सोची-समझी साजिश माना जा रहा है।

समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अन्यथा वेयरहाउस में रखा हजारों मैट्रिक टन गेहूं जलकर राख हो सकता था। आग बुझाने के दौरान पानी का छिड़काव किया गया, जिससे गेहूं की कई बोरियां गीली हो गईं। अब खरीदी

केंद्र से जुड़ी एजेंसी इन बोरियों को सुखाने का काम करेगी।

प्रशासन पर मामला दबाने के आरोप लगे

इधर, जिला प्रशासन पर मामले को दबाने की कोशिश करने के आरोप भी लग रहे हैं। गेहूं खरीदी की नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम, कृषि विभाग और मार्कफेड के अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

पुलिस बोली- सूचना नहीं दी गई

थाना छैगांवमाखन पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले की सूचना नहीं दी गई थी। आग की जानकारी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई थी, जहां से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

मनावर में खरीफ सीजन की तैयारी शुरू, खेतों में जुताई और खरपतवार हटाई जा रही

दैनिक इंदौर संकेत

मनावर ● मनावर और उमरबन के ग्रामीण इलाकों में खरीफ सीजन की आहट के साथ ही खेती-किसानी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। शादियों के सीजन से फुर्सत मिलते ही किसान अब पूरी तरह अपने खेतों को संवारने में जुट गए हैं। निमाड़ अंचल में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके बावजूद किसान राजू देवड़ा और उनके साथी सुबह-शाम खेतों में पसीना बहा रहे हैं। कहीं ट्रैक्टरों से गहरी जुताई हो रही है, तो कहीं पारंपरिक तरीके से खरपतवार हटाई जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्षेत्र के किसान मुख्य रूप से कपास, मक्का और मिर्च की बोवनी की प्रारंभिक तैयारी पूरी कर चुके हैं। अब उनका पूरा ध्यान सोयाबीन की बुवाई के लिए जमीन तैयार करने पर है। किसानों का मानना है कि मानसून की पहली फुहार पड़ते ही अगर बुवाई शुरू हो जाए, तो फसल की पैदावार बेहतर होती है।

बस स्टैंड से पकड़ी 1.37 लाख की शराब, खरगोन के बिस्टान में देर रात कार्रवाई

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● बिस्टान में सोमवार रात बस स्टैंड क्षेत्र से अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। पार्षद और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 लाख 37 हजार रुपए मूल्य की शराब जब्त की। पार्षद रूपेश राठौड़ ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। सोमवार रात लोगों की सूचना पर 10 से अधिक युवकों ने एक संदिग्ध वाहन को रोका और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिना नंबर की जीप की तलाशी ली, जिसमें 41 पेटी देशी-विदेशी शराब मिली। जब्त शराब की मात्रा 354 बल्क लीटर बताई गई है। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जीप में मौजूद मैनेजर अशोक शर्मा भी मौके से भाग निकला। सूत्रों के अनुसार अशोक शर्मा पहले भी भोगर्या पर्व के दौरान भगवानपुरा रोड क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर संदिग्ध रहा है, जिस पर शिकायतों के बाद कार्रवाई भी हुई थी। पुलिस ने फरार चालक के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

आईपीएल में आज होगा आरसीबी और केकेआर का मुकाबला

रायपुर। (एजेंसी) • प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम को अगर अंतिम चार में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित करनी है, तो उसके बल्लेबाजों को बुधवार को रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के सामने आक्रामक प्रदर्शन करना होगा। आरसीबी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले कुछ मैच में उसके बल्लेबाज अपेक्षित खेल नहीं दिखा पाए। पिछले मैच में वह क्रुणाल पांड्या के अर्द्धशतक और अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार के छक्के से ही लक्ष्य तक पहुंच पाई थी।

अब उसके बल्लेबाजों का सामना केकेआर के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण से होगा, जिसमें सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे रहस्यमयी स्पिनर शामिल हैं। उन्हें कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा

और अनुकूल रॉय जैसे घरेलू गेंदबाजों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन से केकेआर ने शुरू में लडखड़ाने के बाद लगातार चार जीत दर्ज की हैं।

सात्विक-चिराग मुश्किल जीत के बाद दूसरे राउंड में

बैंकाक (एजेंसी) • मौजूदा एशियन गेम्स चैंपियन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मंगलवार को निमिबुत्र स्टेडियम में कड़ी टक्कर में जीत के साथ थाईलैंड ओपन 2026 बैटमिंटन कैंपेन की शुरुआत की। बैटमिंटन रैंकिंग में चौथे नंबर पर टॉप सीड सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की अनरैंक्ड जोड़ी पुत्रा एरवियनस्याह और बगास मौलाना को 21-19, 21-23, 21-10 से हराकर दूसरे राउंड में एंट्री की। धीमी शुरुआत के बाद, जिसमें वे 16-11 से पीछे थे, सात्विक-चिराग ने लगातार सात प्वाइंट्स के साथ वापसी की और कंट्रोल हासिल किया और एक कड़े शुरुआती गेम में जीत हासिल की।

कुश्ती महासंघ पर भड़की विनेश , मुझे खेल छोड़ने मजबूर किया जा रहा

गोंडा (एजेंसी) • ओलंपियन महिला पहलवाल विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) पर आरोप लगाये हैं कि उन्हें खेल से बाहर करने के प्रयास चल रहे हैं। विनेश ने कहा है कि कुश्ती महासंघ उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है ताकि वह खेल छोड़ दें। विनेश ने कहा है कि वह इसके बाद भी खेल नहीं छोड़ेगी और अपनी ओर से संघर्ष करती रहेंगी। विनेश का प्रयास गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से वापसी का था पर कुश्ती महासंघ ने उन्हें अयोग्य घोषित कर रोग दिया। महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के तहत संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य छह महीने के नोटिस समय की बात कहते हुए उन्हें 26 जून 2026 तक के लिए अयोग्य ठहराया है। विनेश प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचीं और दावा किया कि वह मुकाबले में वापसी के योग्य हैं पर महासंघ के अधिकारियों ने उनको अवसर देने से साफ इंकार कर दिया। महासंघ के अधिकारियों से मुलाकात के बाद विनेश ने कहा, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या मैं संन्यास ले लूं और दूर हो जाऊं? हार मान लूं? जिससे कि मेरे खिलाफ उनकी साजिश कामयाब हो जाए? वे चाहते हैं कि मैं कुश्ती छोड़ दूं, मैं थक जाऊं, मैं हाथ जोड़ लूं और चली जाऊं।

हर रंग-रूप की अपनी एक कीमत होती है: हिंदी ज़ी5 ने सतरंगी - बदले का खेल का ट्रेलर लॉन्च किया

मुंबई (एजेंसी) • ज़ी5 ने अपनी नई हिंदी मूल ड्रामा श्रृंखला सतरंगी - बदले का खेल का ट्रेलर जारी कर दिया है, यह कहानी ग्रामीण उत्तर प्रदेश के सामंती माहौल पर आधारित है। इस श्रृंखला में अंशुमान पुष्कर, कुमुद मिश्रा, महवश, उपेन चौहान और कशिश दुग्गल मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। श्रृंखला का निर्देशन जय बसंतू सिंह ने किया है और इसका निर्माण आरएनडी फिल्म एलएलपी ने किया है। यह श्रृंखला 22 मई 2026 को प्रदर्शित होगी।

'सतरंगी - बदले का खेल' की कहानी बबलू महतो (अंशुमान पुष्कर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक लौंडा नाच कलाकार के बेटे के रूप में अपमान और चुप्पी के माहौल में बड़ा होता है। जाति और ताकत से बंटी सामंती व्यवस्था में पले-बढ़े बबलू को जल्दी समझ आ जाता है कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सत्ता के खेल को समझकर ही जिया जा सकता है। बबलू और लल्ली के रूप में दोहरी ज़िंदगी जीते हुए, वह दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच अपना रास्ता बनाना शुरू करता है, एक सत्ता की दुनिया, और दूसरी मंच की दुनिया। इसी दौरान वह सिंह और पांडे जैसे दो प्रभावशाली परिवारों के

बीच बेहद खतरनाक खेल की नींव रखता है। जो कहानी शुरुआत में बदले की भावना से शुरू होती है, वह धीरे-धीरे सम्मान, अधिकार, बराबरी और सत्ता पर कब्जे की बड़ी लड़ाई में बदल जाती है।

सतरंगी - बदले का खेल को खास बनाने वाली बातें: ग्रामीण उत्तर प्रदेश की सामंती राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित एक बहुआयामी और दमदार सत्ता की कहानी। लौंडा नाच को सिर्फ सांस्कृतिक कला नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्ष और जीविका के माध्यम के रूप में दिखाया गया है। कहानी का केंद्र एक ऐसा किरदार है, जो बबलू और लल्ली — दो अलग पहचान के साथ दोहरी जिंदगी जीता है। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, बल्कि सम्मान, जाति, नियंत्रण और भावनात्मक संघर्ष जैसे मुद्दों को भी गहराई से दिखाती। इस कहानी के केंद्र में लौंडा नाच की दुनिया है। यह उत्तर भारत की एक पारंपरिक लोक कला है, जिसमें पुरुष महिलाओं के वेश में सामुदायिक समारोहों और उत्सवों में प्रस्तुति देते हैं। ये कलाकार किसी अलग लैंगिक पहचान को नहीं दर्शाते, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। श्रृंखला में लौंडा नाच को केवल सांस्कृतिक कला के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसे पहचान, सम्मान, पुरुषत्व और संघर्ष जैसे विषयों को समझने के माध्यम के रूप में पेश किया गया है। यह कहानी एक ऐसे समाज की झलक दिखाती है, जहां असमानता गहराई से मौजूद है। संवेदनशीलता, मानवीय भावनाओं और गहराई के साथ यह श्रृंखला एक ऐसी दुनिया को सामने लाती है, जिसे बहुत कम दिखाया गया है।

मां बनना जिंदगी का सबसे सुंदर अनुभव : दीपिका सिंह

मुंबई (एजेंसी) • टीवी शो 'मंगल लक्ष्मी' में मंगल का किरदार निभा रहीं अभिनेत्री दीपिका सिंह ने अपने बेटे सोहम को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बताया और कहा कि मातृत्व ने उन्हें जीवन को नए नजरिए से समझना सिखाया है। दीपिका सिंह ने मदर्स डे को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि मां बनना उनकी जिंदगी का सबसे सुंदर और बदलाव लाने वाला अनुभव रहा है। दीपिका सिंह ने कहा कि एक अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन अपने बेटे सोहम की मां बनना उनके जीवन का सबसे खास और सबसे बड़ा किरदार है। उनके अनुसार मां बनना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवनभर चलने वाला भावनात्मक सफर है, जो हर दिन इंसान को कुछ नया सिखाता है।

उज्जैन संभाग

पांच माह के बच्चे को एयर एंबुलेंस से बेंगलुरू भेजा, दिल की बीमारी से है पीड़ित

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • जिले के महिदपुर क्षेत्र के पांच माह के यथार्थ सिंह राणावत को हृदय रोग के इलाज के लिए बेंगलुरु भेजा गया है। बच्चे को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत यह सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं कीं। यह उज्जैन जिले का संभवत: पहला मामला है, जब किसी बच्चे को इलाज के लिए बेंगलुरु भेजा गया है। यथार्थ महिदपुर विकासखंड के ग्राम सनोरिया सुमराखेड़ा निवासी दीपक सिंह राणावत का पुत्र है। वह जन्म से ही हृदय संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसे पहले उज्जैन के तेजनकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद बच्चे में जटिल हृदय रोग का पता चला और सर्जरी की आवश्यकता बताई गई।

आयुष्मान निरामय योजना के तहत यथार्थ के इलाज का खर्च वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों पर, जन्मजात हृदय रोग से ग्रस्त

यथार्थ सिंह राणावत को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस योजना के माध्यम से बेंगलुरु के नारायणा हेल्थ सिटी रेफर किया गया। यह रेफरल 12 मई को सुबह करीब 10 बजे किया गया। बच्चे को पहले एम्बुलेंस से उज्जैन से इंदौर ले जाया गया। इसके बाद, पीएमश्री एयर एम्बुलेंस द्वारा उसे बेंगलुरु पहुंचाया गया। कलेक्टर ने बच्चे को समय पर एयर एम्बुलेंस के जरिए बेंगलुरु पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करवाई।

उज्जैन में पारा 44.4 डिग्री पर, मंगलवार सीजन का सबसे गर्म दिन

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • मंगलवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। शहर में पारा 44.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले सोमवार को तापमान 43 डिग्री था। एक ही दिन में 1.4 डिग्री तापमान बढ़ने से लोग दिनभर गर्मी से परेशान रहे।

गर्मी ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। दिनभर भीषण गर्मी और लू चलने के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। पांच दिन पहले 6 मई को अधिकतम तापमान 39 डिग्री था, लेकिन महज एक हफ्ते में पारा करीब 5 डिग्री बढ़ गया। इससे पहले 25 अप्रैल को 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। सोमवार को पारा 43 डिग्री पर रहा, लेकिन एक दिन बाद ही यह 1.4 डिग्री बढ़कर 44.4 डिग्री पर पहुंच गया।

गर्मी से बचने के लिए कई लोग सिर पर कपड़ा बांधकर निकले, तो कुछ लोग शीतल पेय का सेवन करते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक, इस हफ्ते गर्मी इसी तरह लोगों को परेशान कर सकती है।

जांच टीम पहुंचने से पहले कई डॉक्टर ताला लगाकर भागे, 38 अस्पताल क्लिनिक में बिना रजिस्ट्रेशन के इलाज कर रहे थे

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • 11 वर्षीय छात्रा की ऑपरेशन के दौरान मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। कलेक्टर के निर्देश पर गठित पांच अलग-अलग टीमों ने शहरभर के अस्पतालों और क्लिनिकों की जांच की। कार्रवाई के दौरान 38 अस्पताल और क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होते मिले। सभी को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामला उज्जैन की मंछामन कॉलोनी स्थित जनसेवा नोबल पॉली क्लीनिक का है। यहां महिदपुर तहसील के ग्राम तीलियां खेड़ी निवासी मेहरबान सिंह की 11 वर्षीय बेटी दिव्या सूर्यवंशी का इलाज चल रहा था। दिव्या कक्षा सातवीं की छात्रा थी। रविवार को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए रौशन सिंह ने शहर के सभी अस्पतालों और क्लिनिकों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की पांच टीमों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचकर अस्पतालों और क्लिनिकों की जांच शुरू की। जांच के दौरान रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज और डॉक्टरों की डिग्री की जांच की गई। डॉ. अशोक पटेल ने बताया कि दो दिन की कार्रवाई में रविवार को 10 और सोमवार को 28 अस्पताल एवं क्लिनिक नियम विरुद्ध संचालित पाए गए। सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और वैध पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में पंजीयन नहीं कराने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सीएमएचओ ने बताया कि कई डॉक्टर जांच टीम के पहुंचने से पहले ही अपने क्लिनिक बंद कर मौके से चले गए। ऐसे संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मंगलवार को भी दोबारा जांच अभियान चलाएंगी।

यादव समाज से परिवार को किया निष्कासित, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई रोक

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • जिले की बड़नगर तहसील के ग्राम बंगरेड में यादव (अहीर) समाज के एक युवक ने समाज के पंचों पर सामाजिक बहिष्कार, अपमान और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित नरेंद्र यादव ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे परिवार सहित धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होंगे। नरेंद्र यादव के अनुसार विवाद की शुरुआत डॉक्टर विष्णु प्रसाद यादव के यहां आयोजित एक शादी समारोह से हुई। समारोह में समाज

की ओर से लिए गए 5100 की बजाय 11 हजार चंदे और धर्मशाला किराए को लेकर समाज के वॉट्सऐप ग्रुप में चर्चा चल रही थी। इसी दौरान नरेंद्र यादव ने ग्रुप में टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि किसी से गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर राशि वापस कर देना चाहिए। आरोप है कि इस टिप्पणी के बाद समाज के एक पंच के भाई ईश्वरलाल यादव ने उन्हें वॉट्सऐप कॉल कर अपशब्द कहे और समाज छोड़ने तक की बात कही। नरेंद्र का कहना है कि उन्होंने इस व्यवहार की जानकारी समाज के ग्रुप में भी दी, लेकिन किसी सदस्य ने विरोध नहीं किया। इसके बाद अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी फोन पर गाली-गलौज और धमकियां देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित युवक का कहना है कि बिना उनका पक्ष सुने और बिना निष्पक्ष बैठक किए समाज के वॉट्सऐप ग्रुप में उनके परिवार को समाज से निष्कासित करने का संदेश जारी कर दिया गया। साथ ही गांव में समाज के कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों में उनके परिवार के शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई। नरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि समाज की धर्मशाला के किराए और चंदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं का विरोध करने के कारण कुछ प्रभावशाली पंच उनसे नाराज हो गए थे। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत पहले एसपी कार्यालय में भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में समाज की बैठक हुई, लेकिन उसमें उन्हें बुलाया तक नहीं गया और केवल चंदे की राशि वापस कर मामले को खत्म मान लिया गया।

सेंट्रल जेल क्वार्टर में महिला से रेप, आरोपी जेल प्रहरी का बेटा, तीन वर्ष से कर रहा था दुष्कर्म

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • भैरवगढ़ सेंट्रल जेल परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में रहने वाली एक महिला ने जेल प्रहरी के बेटे पर दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में पदस्थ एक प्रहरी अपने परिवार के साथ जेल क्वार्टर में रहता है। उसके सामने अन्य प्रहरी सत्यनारायण सक्सेना का परिवार रहता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रहरी का बेटा आयुष सक्सेना पिछले तीन वर्षों से उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म कर रहा था। महिला का कहना है कि आरोपी उसे लगातार धमकाता था और विरोध करने पर बदनाम करने की बात कहता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। भैरवगढ़ थाना पुलिस के मुताबिक सोमवार शाम महिला थाने पहुंची और आरोपी आयुष सक्सेना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

निगम के सौर संयंत्र से प्रति वर्ष लगभग 1 लाख कार्बन क्रेडिट का अनुमान

हाल ही में 60 मेगावाट की परियोजना चालू हुई

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के हाल ही में चालू किए गए 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रति वर्ष लगभग 1 लाख कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का अनुमान है। ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से वित्तपोषित इस सौर परियोजना ने बिजली खर्च में पर्याप्त बचत करके तत्काल वित्तीय व्यवहार्यता प्रदर्शित की है। आईएमसी के अतिरिक्त आयुक्त प्रखर सिंह ने बताया, 'स्वच्छता के लिए अपनी स्थापित प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए, आईएमसी अपनी हरित ऊर्जा और जलवायु वित्त पहलों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहा है।'

उन्होंने कहा कि 3 मार्च से अप्रैल 2026 तक, संयंत्र ने हरित ऊर्जा उत्पन्न की जिससे आईएमसी को बिजली बिलों में लगभग 9 करोड़ रुपये की बचत हुई। प्रत्यक्ष बचत के अलावा, परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 90,000 कार्बन क्रेडिट अर्जित होने का अनुमान है, जिससे शहर के जलवायु वित्त पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी। 'आईएमसी की कार्बन क्रेडिट रणनीति को वेरिफाइड कार्बन स्टैंडर्ड (वीसीएस) कार्यक्रम के तहत पंजीकृत विभिन्न अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन प्राप्त है। इनमें देवगुराड़िया में 600 टीपीडी ठोस अपशिष्ट खाद संयंत्र और दो बायो-मेथेनेशन संयंत्र शामिल हैं। इसके अलावा, 2022 से चालू 550 टीपीडी बायो-सीएनजी संयंत्र ने 2025 के अंत तक लगभग 1,33,041 कार्बन क्रेडिट के कुल उत्सर्जन में कमी हासिल की है,' उन्होंने कहा।

दीर्घकालिक स्थिरता और सटीक कार्बन लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए, आईएमसी ने आईआईटी इंदौर और आईआईएम इंदौर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं। ये साझेदारियां जलवायु-वित्त मॉडलिंग, डेटा सत्यापन और वैज्ञानिक प्रलेखन पर ध्यान केंद्रित करेंगी क्योंकि शहर अगली पीढ़ी के अपशिष्ट प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सीबीएसई के 12वीं रिजल्ट पर असमंजस

इंदौर सहित कई केंद्रों पर कॉपियां अभी भी जंच रही

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट को लेकर देश भर में 18 लाख से ज्यादा छात्र इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार 10 मई को और तब बढ़ गया जब सीबीएसई ने डीजीलॉकर पर संदेश दे दिया कि रिजल्ट कमिंग सून। इसके बाद कयास थे कि 12वीं का रिजल्ट सोमवार 11मई को आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। इसके बाद अब मंगलवार 12 मई को आने की बात कही जा रही है।

इंदौर में जंच रही कॉपियां-सूत्रों के मुताबिक इंदौर में सोमवार को ही इकोनॉमिक्स विषय की कुछ कॉपियां जंचने के लिए आई हैं। ऐसा ही अन्य विषयों को लेकर देश के अन्य शहरों में भी कॉपियां पहुंची हैं। एक शिक्षक ने बताया कि सीबीएसई द्वारा लगातार संदेश आ रहे हैं कि कॉपियां जल्द चेक करें, इन्हें 12 मई तक किसी भी हाल में करने के लिए कहा गया है। यदि यह मान भी लें कि आज चेक हो जाएंगी तो भी जानकारों के मुताबिक एक दिन तो सभी रिकॉर्ड चेक करने में लगेगा। यानी इस रिजल्ट का मंगलवार को आना मुश्किल है। यह 13 मई को ही संभव हो सकेगा। वैसे भी सीबीएसई ने सभी सेंटर को यह सूचित किया हुआ है कि रिजल्ट 20 मई के पहले आएगा। यानी उस हिसाब से देखें तो डेडलाइन में समय है।

रिजल्ट आने पर यहां देख सकेंगे

रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा। छात्र डिजीलॉकर या फिर UMANG ऐप पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। डिजीलॉकर में Coming Soon वाला मैसेज फ्लैश हो रहा है। इस साल 17 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई थीं, जो 10 अप्रैल तक चलीं थी। कॉपी चेक करने के लिए बोर्ड ने पहली बार ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है।

आईडीए की ईवी पहल बनी प्रदेश में मिसाल हर महीने हजारों लीटर ईंधन की बचत

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● बढ़ते ईंधन संकट और पर्यावरण संरक्षण की चुनौती के बीच इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने ऐसा कदम उठाया है, जो प्रदेश के अन्य सरकारी संस्थानों के लिए उदाहरण बनता जा रहा है। आईडीए प्रदेश में पहला ऐसा सरकारी संस्थान बन गया है, जहां पर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का उपयोग शुरू किया गया है। इससे हर माह हजारों लीटर ईंधन की बचत हो रही है। ऐसी ही पहल इंदौर के सभी शासकीय कार्यालय करने लगे तो ईंधन की बढ़ी बचत हो सकती है। दरअसल एक जनवरी से शुरू किए गए इस नवाचार के तहत वर्तमान में 13 ईवी वाहन विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में लगाए गए हैं। इन वाहनों के उपयोग से हर माह करीब साढ़े तीन हजार से चार हजार लीटर तक पेट्रोल-डीजल की बचत हो रही है। खास बात यह है कि अगले माह 10 और ईवी वाहन शामिल किए जाने की तैयारी है, जिससे बचत का आंकड़ा और बढ़ेगा।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आह्वान किया था। आइडीए के इस दिशा में किए गए प्रयास यह संदेश देते है कि सरकारी संस्थान चाहें तो बड़े स्तर पर बदलाव संभव है। आइडीए सीइओ डा. परीक्षित झाड़े ने आइडीए की कमान संभालने के बाद इस नवाचार को अपने का निर्णय लिया, ताकि ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी सहेजा जा सके।

ईंधन बचत का प्रभावी मॉडल

वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों और पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बीच आईडीए का यह प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ ईंधन बचत का भी प्रभावी माडल बन रहा है। वर्तमान में शहर के कई बड़े सरकारी विभागों जैसे प्रशासनिक संकुल, नगर निगम और पुलिस विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों में अब भी पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों का अधिक उपयोग हो रहा है इसमें हजारों लीटर पेट्रोल-डीजल की खपत होती है।

देपालपुर वार्ड क्रमांक 6 में उल्टी होने के बाद दो मासूम बहनों की मौत

मौत के बाद क्षेत्र में मचा हड़कम कही घंटों बाद जागा स्वास्थ्य विभाग

निलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर ● दैनिक इंदौर संकेत

नगर में स्थित वार्ड क्रमांक 6 दो मासूम बहनों की उल्टियां होने के बाद मौत हो गई प्राप्त जानकारी के अनुसार आरती और खुशबू बार बार पानी पीने के उल्टियां होने लगी परिजन एक बेटी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया वहीं दूसरी बालिका ने अपने घर पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से नगर में हड़कम मच गया इतना ही नहीं इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इस घटना को लेकर वार्ड 6 की जनता में भारी आक्रोश है। घटना घटित होने के बाद कुंभकरण की नींद सोया स्वास्थ्य विभाग जागा और मौके पर पहुंच कर सैंपल लिए गए जांच की गई साथ ही जिला चिकित्सालय अधिकारी माधव सिंह आसानी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वंदना केसरी इस मामले में नजर बनाए

हुए हैं उन्होंने कहा जरूरत पड़ने पर मरीजों को इंदौर रेफर किया जाएगा जानकारी में पता चला वार्ड 6 में और भी 5 से 6 मैरिज बीमारी से पीड़ित है। वार्ड 6 के निवासी जितेंद्र ने बताया कि नाली का चैंबर कहीं महीनो से खुला पड़ा था। यहां गंदा और बदबूदार पानी पड़ा था। जिससे क्षेत्र में बीमारी फैली है महीनो से यहां साफ सफाई नहीं हुई, मासूम बहनों की मृत्यु के बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे वार्ड के अंदर 5 से 6 जगह नाली के गड्ढे खुले पड़े हैं। घटना के बाद नगर में आक्रोश है परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है परिजन ने आरोप लगाया है कि वार्ड में खुले पड़े गड्ढों के कारण ही क्षेत्र में बीमारी फैली है उल्टियां और दस्त होना शुरू हो गए इतनी बड़ी घटना के। बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे एक तरफ तो स्वच्छता का ढिंढोरा पीट रहे जनप्रतिनिधि और दूसरी और वाईवाई लूटने में लगे अधिकारी इन दो मासूम बहनों की मौत का जिम्मेदार कौन है लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरेगी या फिर छोटी-मोटी कार्यवाही कर मामले को दबा दिया जाएगा। परिजन ने दोनों मासूम बहनों का पोस्टमार्टम करवाया और दोनों बहनों का विसरा जांच में भेजा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा।

चोरों ने हनुमान मंदिर में रखी दान पेटी को भी नहीं छोड़ा

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र स्थित एक मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाश मंदिर की दानपेटी का ढक्कन खोलकर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदिर के पुजारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

तिलक नगर पुलिस ने विजय त्रिवेदी निवासी पवनपुरी कॉलोनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। विजय ने पुलिस को बताया कि वह बृजेश्वरी मेन स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर में पुजारी हैं। सोमवार रात वह रोज की तरह मंदिर में ताला लगाकर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह उन्हें सुनील मालवीय का फोन आया, जिसमें बताया गया कि किसी अज्ञात बदमाश ने मंदिर की दानपेटी का ढक्कन उठाकर उसमें रखे रुपए निकाल लिए हैं। घटना के बाद मंदिर से जुड़े लोगों में नाराजगी है। पुजारी के अनुसार, दानपेटी पिछले तीन महीने से नहीं खोली गई थी और उसमें करीब 50 हजार रुपए होने का अनुमान है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भागीरथपुरा कांड : मिली जिम्मेदारों को क्लीन चिट!

संगठन ने फिर सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी, चार माह बाद भी जलकार्य प्रभारी के प्रति नरमी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● भागीरथपुरा कांड में पार्षद कमल बाघेला को संगठन स्तर पर क्लीन चिट मिल गई हैं। उन्हें पिछले दिनों नगर निगम में फिर से भाजपा पार्षद दल का सचेतक नियुक्त किया गया हैं। इसी तरह जलकार्य समिति प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू के मामले में भी संगठन का रूख नरम हैं। इसके चलते वे अपने विभाग में दोगुने उत्साह से जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी में लगातार दौरे कर रहे हैं और अधिकारियों से भी फीडबैक ले रहे हैं। वैसे हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका लगाई गई हैं, उसमें बाघेला और बबलू को भी दोषी बताया गया है। साल 2025 के अंत में भागीरथपुरा कांड सुर्खियों में आया था और नए साल के शुरुआती माह जनवरी में ये देश-प्रदेश में छा गया था। भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से करीब 40 लोगों की मौत हुई थी, वहीं सैकड़ों बीमार हुए थे। इस मामले में इंदौर नगर निगम की जमकर फजीहत हुई थी, भाजपा बचाव की स्थिति में थी, और कांग्रेस ने आक्रामक रूख अपना रखा था। कांग्रेस ने मौन मार्च निकाला था, वहीं राहुल गांधी ने भी भागीरथपुरा में पीड़ित और प्रभावित परिवारों से भेंट की थी। वैसे नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले दिन से ही प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करने में जुटे हुए थे, वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कई बार यहां का दौरा किया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार राहत कार्यों पर नजर रखें हुए थे। हालांकि स्थानीय लोगों में आक्रोश भी कम नहीं था, खासकर नगर निगम और पार्षद कमल बाघेला को लेकर इनमें खासी नाराजगी थी, और कांग्रेस इसमें आग में घी काम कर रही थी।

दोगुने उत्साह में बबलू-जलकार्य प्रभारी के नाते अभिषेक शर्मा बबलू भी खासे निशाने पर थे, क्योंकि पेयजल वितरण से लेकर नई लाइन डालना व लाइनों को बदलना उनके विभाग के अंतर्गत ही आता हैं। बबलू को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी थी। वे कांग्रेस के साथ ही अपने दल में भी निशाने पर थे, लेकिन उनके मामले में भी पार्टी का नरम रूख हैं, क्योंकि चार माह बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं, और ना ही संगठन के किसी नेता ने उन्हें तलब किया हैं। इन दिनों बबलू दोगुने उत्साह से जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी में वे जल संकट पर लगातार नजर रखे हुए हैं और दौरे भी कर रहे हैं। भागीरथपुरा कांड के बाद बबलू की कार्यशैली भी खासी बदली हुई हैं।

चुनाव में संगठन करेगा परहेज-दरअसल बाघेला और बबलू के मामले में संगठन का नरम रूख इसलिए भी हैं कि अगर इन पर कोई कार्रवाई होती तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी कटघरे में होते, क्योंकि शीर्ष स्तर पर नगर निगम का नेतृत्व वे ही कर रहे हैं।

डेली कॉलेज को लेकर लगी चार याचिकाओं पर टली सुनवाई

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर डेली कॉलेज बोर्ड के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच सभी की नजरें मंगलवार को हाईकोर्ट पर थीं, लेकिन इस मामले में सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख 14 मई लगा दी गई है। इसके पहले 28 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और इसमें पक्षकारों से जवाब मांगते हुए दो सप्ताह बाद की तारीख लगाई थी। इसमें एक नई याचिका जय सिंह झाबुआ द्वारा लगाई गई है। वहीं डेली कॉलेज सोसायटी, विक्रम खंडेलवाल, संदीप पारिख की ओर से भी याचिकाएं लगी हैं। खंडेलवाल की ओर से दो याचिकाएं हैं। इस तरह कुल पांच याचिकाएं लिंक हैं। इन सभी में मुख्य रूप से फर्म एंड

सोसायटी और डेली कॉलेज बोर्ड पक्षकार हैं। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से नए संविधान को लागू करने और चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां ली गई हैं। इसमें डेली कॉलेज के पूर्व छात्र द्वारा चुनाव पर रोक की मांग की गई है। बीती सुनवाई के दौरान चुनाव पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन इसमें डेली कॉलेज को जवाब देने के लिए समय दिया गया था और स्टे नहीं हुआ था। अब 14 मई की सुनवाई पर नजरें रहेंगी, क्योंकि चुनाव 21 मई को होना है और इसी दिन रिजल्ट भी जारी होगा। नए संविधान के मुताबिक टू बी वन (फाउंडर मेंबर) कैटेगरी से दो सदस्य और टू बी टू (न्यू डोनर) कैटेगरी से एक सदस्य का चुनाव होना तय है।

अब ओडीए में चुनाव नहीं

पुराने संविधान के मुताबिक पहले ओडीए (ओल्ड डेलियंस एसोसिएशन) की टू सी कैटेगरी से भी दो सदस्यों का चुनाव होता था। लेकिन अब नए संविधान में सीधे चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। अब प्रावधान है कि प्राथमिकता से ओडीए के प्रेसीडेंट और सचिव को बोर्ड में लिया जाएगा और एक सदस्य, जो पूर्व प्रतिष्ठित छात्र होगा, उसे लिया जाएगा। इस तरह ओडीए से तीन सदस्य बोर्ड में जाएंगे, लेकिन सीधे चुनाव की जगह अब चयन होगा। इसी बदलाव का सबसे ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है।

इंदौर में बीईओ पद बना 'कांटों की कुर्सी' जिम्मेदारी लेने को कोई नहीं तैयार

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय में हाल ही में सामने आए आर्थिक घोटाले और इस मामले में कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप की स्थिति है। करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने न केवल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अब इस पद पर बैठने को लेकर भी अधिकारियों में डर का माहौल बन गया है।

सूत्रों के अनुसार, घोटाले के उजागर होने के बाद बीईओ कार्यालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई प्राचार्यों से चर्चा की गई, लेकिन अधिकांश अधिकारियों ने इस पद पर आने में अनिच्छा दिखाई। अधिकारियों का मानना है कि पहले से विवादों में घिरे कार्यालय की जिम्मेदारी लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है। विभागीय स्तर पर भी जांच जारी है और पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक सप्ताह में इस पद पर नियुक्ति हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस 'कांटों की कुर्सी' पर बैठने का जोखिम कौन उठाएगा।

मास्टर माइंड अभी भी पहुंच से दूर

सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस कार्यालय में कर्मचारियों का एक समूह ऐसा है जो इस तरह के घोटालों के मास्टर माइंड है लेकिन वे सामने नहीं आते है। जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए है वे तो एक मोहरा है। कथित तौर पर अभी इस घोटाले का मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा है। अधिकांश प्राचार्य जो वरिष्ठता की सूची में इस मास्टरमाइंड की हरकतों से वाकिफ है लेकिन विभागीय गरिमा के चलते चुप्पी साधे हुए है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।